श्रावण मास, कृष्ण पक्ष 1 वर्ष, अंक 21, पृष्ठ 4, मूल्य 1.00

अखण्ड भारत सन्देश

www.akhandbharatsandesh.net

प्रयागराज से प्रकाशित

नगर संस्करण | प्रयागराज | गुरूवार, 27 अगस्त, 2020

विश्व निर्माण एवं मानव विकास को द्रुतगति प्रदान करने हेतु क्रियायोग आश्रम एवं अनुसंधान संस्थान की एक अनुपम भेंट

नीट और जेइइ मेन की परीक्षा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं सात मुख्यमंत्री

नई दिल्ली, एएनआइ। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, झारखंड के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक की। बैठक में NEET-JEE MAIN परीक्षा कराने के फैसले के खिलाफ सात राज्?यों के सुप्रीम कोर्ट जानें पर आम सहमति बनी। बैठक में इस बात पर सहमति बनी है कि NEET-JEE MAIN परीक्षा कराने के केंद्र के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नीट-जेइइ का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार को लगता है कि वो नीट और जेइइ की परीक्षा को स्थगित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं करेगी तो हम (राज्य सरकारें) संयुक्त रूप से सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। परीक्षाएं सितंबर में हैं। छात्रों के जीवन को जोखिम में क्यों डाला जाना चाहिए? हमने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं आइ। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उनका समर्थन किया। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने से पहले हमें प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के पास जाना चाहिए।

इससे पहले मीटिंग में सोनिया गांधी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) पर भी चिंता जताई। उन्होंने

इसे लेकर कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति संबंधी घोषणाओं से हमें सच में चिंतित होना चाहिए क्योंकि यह वाकई बड़ा झटका है। विद्यार्थियों और परीक्षाओं से संबंधित समस्याओं पर भी बहुत लापरवाही भरा रवैया सामने आ रहा है। उन्होंने जीएसटी कंपनसेशन देने पर केंद्र सरकार की तरफ से व्यक्त की गई असमर्थता को राज्यों के साथ विश्वासघात करार दिया। उन्होंने कहा कि11 अगस्त को वित्त मामलों पर स्थायी समिति की मीटिंग में वित्त सचिव ने कहा था कि केंद्र सरकार इस वर्ष 14% जीएसटी कंपनसेशन का भुगतान करने की स्थिति में नहीं है। यह इनकार मोदी सरकार की तरफ विश्वासघात के सिवा और कुछ नहीं है।'

बता दें कि यह बैठक जीएसटी मुआवजे, नीट-जेईई की परीक्षाओं सहित कई अन्य मुद्दों को लेकर बुलाई गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी वर्चुअल मीटिंग में शामिल हुए। इस दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि एक रिपोर्ट में यह बात सामने आई थी कि अमेरिका में स्कूल खोलने पर लगभग 97,000 बच्चे कोरोना से संक्रमित हुए थे। अगर ऐसी स्थिति यहां आएगी तो हम क्या करेंगे? वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि कोरोना के कारण स्थिति खराब हो रही है। हमने लगभग 500 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। हम ऐसी स्थिति में हैं जहां हमारे राज्यों की वित्तीय स्थिति पूरी तरह से खराब है। केंद्र ने जीएसटी मुआवजा नहीं दिया है। मैं ममता जी से सहमत हूं कि हमें सामूहिक रूप से पीएम से बात करनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार ने पिछले 4 महीनों से राज्यों को जीएसटी मुआवजा नहीं दिया है। आज स्थिति भयावह है।

पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी ने कहा कि देश में परीक्षाओं के आयोजन से कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि होगी। भारत सरकार इसके लिए जिम्मेदार होगी। हम इस मुद्दे पर संयुक्त रूप से केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे।

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने एक अगस्त को कहा कि कुल जीएसटी कलेक्शन 87,422 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल से 14 फीसद कम रहा। इसमें से सेंट्रल जीएसटी के तौर पर 16,147 करोड़ रुपये, स्टेट जीएसटी के तौर पर 21,418 करोड़ रुपये शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षाओं को स्थगित करने की याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट द्वारा परीक्षाओं को स्थगित करने की याचिका खारिज होने के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 1 सितंबर से 6 सितंबर के बीच जेईई और 13 सितंबर को नीट की परीक्षाएं आयोजित कराने की घोषणा की। कई मुख्यमंत्री परीक्षा आयोजित करने के केंद्र के फैसले का विरोध करते रहे हैं। इससे पहले दिन में, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा कि केंद्र सरकार से नीट और जेईई परीक्षाओं की तारीखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक समीक्षा याचिका दायर करने पर विचार करने का आग्रह किया।

देश में पुरातात्विक स्थलों की देखभाल के लिए मेरठ झांसी सहित सात और नए सर्कल होंगे गठित

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। पुरातात्विक स्मारकों के संरक्षण और उनके पंजीकरण की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए संस्कृति मंत्रालय ने मेरठ, झांसी, जबलपुर सहित देश में सात और नए सर्कल के गठन का फैसला लिया है। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने बुधवार को इसकी घोषणा की। मौजूदा समय में पुरातात्विक स्थलों की देखभाल के लिए देश में कुल 29 सर्कल है। इनमें से अकेले उत्तर प्रदेश में तीन सर्कल थे। जिसमें लखनऊ, आगरा और सारनाथ सर्कल शामिल है। जो अब बढ़कर पांच हो गए है।

केंद्रीय संस्कृति मंत्री ने बताया कि

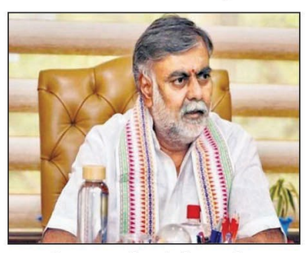

पुरातात्विक स्थलों की बेहतर देखभाल के लिए एएसआई के सर्कल का पुनर्गठन किया गया है। जिसमें उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में झांसी में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का नया सर्कल गठित होगा। इस तरह मध्य प्रदेश में जबलपुर को एक नया सर्कल बनाया गया है। जिसके क्षेत्र में जबलपुर, रीवा, शहडोल और सागर संभाग के स्मारकों को शामिल किया गया है। अभी तक यह सभी एएसआई के भोपाल सर्कल में आते है। इसके साथ ही गुजरात के राजकोट को, पश्चिम बंगाल के रायगंज को, तमिलनाडु के त्रिची को नया सर्कल बनाया गया है। वहीं कर्नाटक के हम्पी को जो अब तक उप-सर्कल था, उसे अब नया पूर्ण सर्कल बना दिया गया है। मंत्रालय के मुताबिक नए सर्कल के गठन का फैसला पुरातात्विक स्मारकों के बेहतर देखभाल के लिहाज से लिया गया है। अभी इन सर्कल का दायरा इतना लंबा था, कि जहां से दूर-दराज के क्षेत्रों से स्थित स्मारकों का ठीक तरीके देखभाल नही हो पा रहा था।

यूपी में संक्रमित मरीजों की संख्या दो लाख के पार

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। रोजाना औसतन 5000 हजार नए कोरोना मरीज सामने आ रहे हैं। बुधवार को प्रदेश में 5898 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले जिसके बाद अब यूपी में कोरोना संक्रमित हो चुके मरीजों की संख्या दो लाख के पार पहुंच चुकी है। इस दौरान प्रदेश में 82 कोरोना मरीजों की मौत भी हुई।

यह जानकारी अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी व अपर मुख्य सचिव चिकित्सा अमित मोहन प्रसाद ने दी। उन्होंने बताया कि बुधवार को प्रदेश में सबसे ज्यादा 1.44 लाख टेस्टिंग हुई हैं। इस इस वक्त प्रदेश में 51,317 एक्टिव मामले हैं जिसमें से 25,279 होम आइसोलेशन में हैं। 58,296 की अवधि खत्म हो चुकी है।

अब तक 83,575 मरीज होम आइसोलेशन का फायदा उठा चुके हैं। इस समय 2341 प्राइवेट अस्पतालों और 250 एल-1 प्लस की सुविधा वाले होटलों और गेस्ट हाउसों में हैं।

लखनऊ में सबसे ज्यादा 759 संक्रमित मिले

बुधवार को लखनऊ में सबसे ज्यादा संक्रमित मामले 759 मिले जबकि सबसे ज्यादा 9 मौतें गोरखपुर में हुई। बुधवार को हुई 82 मौतों में सबसे ज्यादा गोरखपुर में नौ, लखनऊ में आठ, सहारनपुर में छह, महाराजगंज में पांच कोरोना मरीजों की मौत हुई। इसके अलावा कानपुर, वाराणसी और मुरादाबाद में 4-4, प्रयागराज, बरेली, बाराबंकी, शाहजहांपुर, बस्ती और रायबरेली में 3-3, झांसी, मेरठ, पीलीभीत, इटावा और सोनभद्र 2-2 जबकि नोएडा, अयोध्या, रामपुर, गोंडा, हरदोई, बुलंदशहर, मथुरा, सुलतानपुर, संतकबीरनगर, हापुड़, बदायूं, मैनपुरी, जालौन और श्रावस्ती में 1-1 मौत हुई है।

कोरोना मरीजों को अस्पताल भेजने में देरी की तो होगी कार्रवाई

निजी अस्पतालों में भर्ती सामान्य मरीज के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद कोविड अस्पताल में भेजने की प्रक्रिया लम्बी है। जब तक उसे कोविड अस्पताल भेजा जाता है, उसकी हालत बिगड़ चुकी होती है। ऐसे कुछ मामले सामने आए जिसके बाद बुधवार को लखनऊ के डीएम ने 12 प्रमुख निजी अस्पतालों के प्रबंधन को बुलाया और निर्देश दिया कि एक रिजर्व एम्बुलेंस रखें। कोविड अस्पताल भेजने की प्रक्रिया में देरी न हो। लापरवाही दिखी तो संबंधित अस्पताल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अस्पताल का पंजीकरण भी निरस्त कर दिया जाएगा।

केंद्र सरकार ने कंक्रीट की सड़क बनाने पर लगाई रोक

रायपुर, राज्य ब्यूरो। देश में अब कंक्रीट की सड़कें नहीं बनेंगी। छत्तीसगढ़ के लोक निर्माण विभाग के मंत्री ताम्रध्वज साहू ने बताया कि कंक्रीट की सड़क बनाने का फैसला केंद्र सरकार का था, लेकिन पूरे देश में इससे बनी सड़कें खराब हो रही थीं। ऐसे में केंद्र सरकार के पास कई राज्यों से इसकी शिकायतें पहुंच रही थीं। इसी आधार पर केंद्र सरकार ने कंक्रीट और सीमेंट की सड़कें बनाने के आदेश को निरस्त कर दिया है। छत्तीसगढ़ के लोक निर्माण विभाग के मंत्री ताम्रध्वज साहू ने विधानसभा में दी जानकारी छत्तीसगढ़ की विधानसभा में बुधवार को प्रश्नकाल के दौरान मंत्री साहू ने बताया कि सीमेंट की सड़कों में जगह-जगह दरारें पड़ जाती हैं। इससे सड़कों पर गढ्डे हो जाते हैं। गढ्डों को ठीक

करने के लिए सड़क के पूरे हिस्से को काट कर निकालना पड़ता है और नए सिरे वहां कंक्रीट का हिस्सा बनाना पड़ता है। इन्हीं समस्याओं की वजह से कंक्रीट की सड़क बनाने के आदेश को निरस्त किया गया है ।लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र में खराब सड़कों को लेकर विधायक डॉ. प्रीतम राम ने बुधवार को यह मामला सदन में उठाया था। डॉ. प्रीतम ने अधूरे कार्य को लेकर प्रश्न किया था। उन्होंने कहा कि सड़कों के पैचवर्क का जो कार्य किया जा रहा है, उसकी गुणवत्ता ठीक नहीं है। इस पर नियंत्रण रखना चाहिए। इसके जवाब में मंत्री साहू ने कहा कि सड़कों में लगातार पेचवर्क किया जा रहा है। जहां काम चल रहा है, वहां फोटो खींचकर अपलोड कराना शुरू किया है। यदि कोई ठेकेदार गलत कार्य करेगा, तो उसकी जांच करके कार्रवाई करवाएंगे। हमारी मंशा अच्छा काम कराने की है।

प्रश्न पर चर्चा के दौरान बिलासपुर-रायपुर राष्ट्रीय राजमार्ग को लेकर विधायक धर्मजीत सिंह ने कहा कि सड़क में बड़े-बड़े गढ्ढे हैं। ब्रिज के दोनों ओर जर्क लगता है। लोगों की रीढ़ की हड्डी तक हिल जाती है। कुछ दिनों पहले ही दो लोगों की मौत हुई है। मंत्री साहू ने कहा कि सीमेंट की सड़कों में जर्क की समस्या है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से बात की है। खराब सड़कों की मरम्मत के लिए प्रस्ताव भेजा गया है।

सेवानिवृत्ति के बाद सम्मानपूर्वक जीने का हक है पेंशन इससे वंचित नहीं किया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, पीटीआइ। सुप्रीम कोर्ट ने पेंशन को सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार माना है। शीर्ष कोर्ट ने कहा है कि पेंशन सेवानिवृत्ति के बाद की अवधि के लिए सहायता है न कि इच्छा होने पर कोई कृपा। यह कर्मचारी के लिए सेवानिवृत्ति के बाद सम्मान बनाए रखने के अधिकार के तौर पर किया गया एक सामाजिक कल्याण उपाय है। केरल के एक सेवानिवृत्त कर्मचारी की पेंशन में विसंगति दूर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा, पेंशन सुविधा सरकारी कर्मचारी को ढलती उम्र में सम्मान के साथ जीने के लिए है और इसलिए किसी कर्मचारी को इस लाभ से अकारण वंचित नहीं किया जा सकता। शीर्ष अदालत ने कहा कि इसमें किसी भी नियम आदि का बहाना नहीं बनाया जाना चाहिए। कर्मचारी का पक्ष लेते हुए जस्टिस एसके कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने केरल सरकार को पेंशन लाभ का निर्धारण करने में अनुबंधित कामगार के रूप में दी गई उसकी सेवा अवधि को भी शामिल करने का आदेश दिया। कर्मचारी ने दावा किया था कि सरकारी विभाग में 32 साल तक काम करने के बावजूद उसे अंतिम 13 साल के लिए ही पात्र माना गया है। सुनवाई कर रही पीठ में जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस अनुरुद्ध बोस भी शामिल थे। पीठ ने ब्याज के साथ पेंशन का बकाया आठ सप्ताह में भुगतान करने का आदेश दिया है।

इसके अलावा लोन मोरेटोरियम अवधि (छङ्कल्ल टङ्ग१३ङ्ग१४ ढी१ङ्ग) में ईएमआई पर ब्याज में छूट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से 1 सितंबर तक जवाब तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को फटकार लगाते हुए कहा कि 'आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पीछे नहीं छुप सकते और केवल व्यापार का हित नहीं देख सकते हैं। सरकार को लोगों की दुर्दशा के बारे में भी सोचना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना संकट को देखते हुए लोन की ईएमआई को स्थगित किए जाने के फैसले के बीच इस पर ब्याज को माफ करने के मसले पर केंद्र की कथित निष्क्रियता पर सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि डीएम एक्ट के तहत केंद्र के पास पर्याप्त शक्तियां हैं और उसको स्थिति स्पष्ट करनी ही होगी।

मॉर्चरी में रिया के प्रवेश पर महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोग का मुंबई पुलिस और अस्पताल को नोटिस

मुंबई, एजेंसियां। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोग भी सक्रिय हो गया है। उसने बुधवार को मुंबई पुलिस एवं कूपर अस्पताल को नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि किस नियम के तहत रिया चक्रवर्ती को अस्पताल की मॉर्चरी में प्रवेश की इजाजत दी गई।

सीबीआइ की विशेष टीम पूछताछ के दौरान सुशांत के फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी से अभिनेता के यूरोप दौरे से लौटने के बाद के घटनाक्रम के बारे में जानना चाह रही है। सुशांत पिछले साल अक्टूबर में गर्लफ्रेंड रिया के साथ यूरोप के दौरे पर गए थे। उधर, पूर्व नौकरशाह आरवीएस मणि ने कहा कि सुशांत व दिशा सालियान की मौत के तार बॉलीवुड, क्रिकेट व दुबई से जुड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह गंभीर मामला है और जांच के दौरान इन पहलुओं पर भी गौर किया जाना चाहिए। सुशांत के पिता केके सिंह के वकील विकास सिंह ने बुधवार को कहा, 'ऐसा लगता है कि सुशांत को काबू में रखने के लिए उनकी जानकारी के बिना गर्लफ्रेंड रिया उन्हें ड्रग्स देती थी। उन्होंने कहा, 'जब परिवार ने मुकदमा दर्ज कराया था तब यह आशंका थी कि सुशांत ड्रग्स के ओवरडोज के शिकार थे, लेकिन अब लगता है कि उन्हें जानबूझकर काबू में रखने के लिए रिया प्रतिबंधित ड्रग्स देती थी।'

एमपी का लाल बारामूला में शहीद, एक करोड़ रुपये के सम्मान निधि का एलान

भोपाल, एएनआइ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजगढ़ जिले के वीर सैनिक मनीष विश्वकर्मा कारपेंटर के पार्थिव शरीर पर भोपाल में पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मनीष कश्मीर में बारामूला के संघर्ष में जवाबी फायर करते हुए शहीद हुए थे।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि शहीद परिवार को एक करोड़ की सम्मान निधि, परिवार के एक सदस्य को उनकी सहमति पर शासकीय सेवा में नियुक्ति, ग्राम में शहीद की प्रतिमा की स्थापना और किसी संस्था का नाम शहीद के नाम पर किया जाएगा।

वहीं ,शोक जताते हुए मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके कहा था, ₹राजगढ़ के खुजनेर की माटी के लाल, वीर सपूत मनीष कारपेंटर जी कश्मीर के बारामूला में हुए आतंकी हमले में शहीद हो गए। ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और परिजनों को यह गहन दुःख सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना करता हूं। मध्यप्रदेश को अपने वीर सपूत पर गर्व है।

मिली जानकारी के मुताबिक, मनीष कश्मीर में बतौर सैनिक के रूप में तैनात थे। शुक्रवार को वह आतंकियों द्वारा जमीन में लगाए गए बम का शिकार हो गए। उनका पैर जमीन में दबे बम पर रखने से चार जवान घायल हुए थे। इसके बाद सभी को श्रीनगर के अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन रविवार को मनीष ने दम तोड़ दिया।

कोरोना संकट को देखते हुए राजगढ़ जिले के तकरीबन 400 से ज्यादा ग्राम पंचायत सचिव, जीआरएस एवं सरपंच आदि को जिला पंचायत सीइओ आशीष सांगवान द्वारा शहीद को ऑनलाइन तरीके से श्रद्धांजलि दिलवाई गई। इस मौके पर सभी से ई-चौपाल के माध्यम से बात भी की गई। मनीष कारपेंटर के पार्थिव शरीर को उनके निवास स्थान खुजनेर पहुंचने पर ऑनलाइन श्रद्धांजलि दिलवाई गई। जिला पंचायत सीइओ द्वारा दोपहर एनआइसी लिंक के जरिए 400 से अधिक ग्राम पंचायत प्रधानों, सचिवों, आम ग्रामीणों से पहले ई-चौपाल द्वारा चर्चा की गई। इसके बाद शहीद को श्रद्धांजलि दी गई। यह पहला मौका था जब सबसे पहले इतनी अधिक संख्या में श्रद्धांजलि दी गई।

समय पर ही होंगी जेईई मेंस और नीट की परीक्षाएं, प्रवेश पत्र जारी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। इंजीनियरिंग में प्रवेश के लिए होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई) मेंस और मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) टालने के लिए कुछ छात्रों के साथ-साथ विपक्षी राजनीतिक दलों ने भले मोर्चा खोल दिया है, लेकिन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) के बढ़े कदम अब रुकने वाले नहीं हैं। एनटीए ने साफ कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद परीक्षाओं में अब कोई भी बदलाव संभव नहीं है। यह तय तारीखों पर ही होगी। परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग को लेकर छात्रों का एक वर्ग मोर्चा खोले हुए है जिसे कांग्रेस और दूसरे विपक्षी राजनीतिक दलों का भी समर्थन मिल रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को भी ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा और मांग की कि सभी पक्षों से बातचीत कर इसका समाधान निकाला जाए। इससे पहले महाराष्ट्र, ओडिशा, बंगाल और दिल्ली जैसे राज्य परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग कर चुके हैं। वहीं शिक्षा मंत्रालय के सूत्रों की मानें तो जो लोग परीक्षाओं को स्थगित या रद्द करने की मांग कर रहे है, वह

निजी शैक्षणिक संस्थान चलाने वाले एक वर्ग को फायदा पहुंचाना चाहते है। सत्र में बहुत वक्त नहीं बचा है और ऐसे में परीक्षा टलती है तो निजी संस्थानों को मनमाने तरीके से एडमिशन देने का अवसर मिल सकता है।

बहरहाल एनटीए का कहना है कि जो लोग कोरोना संक्रमण का हवाला देकर इन परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग कर रहे है, उनकी मांग पर पहले भी दो बार इन परीक्षाओं को टाला जा चुका है, लेकिन अब इन परीक्षाओं को टालना इसलिए भी संभव नहीं है, क्योंकि इसके बाद शैक्षणिक संस्थानों के लिए नया सत्र शुरू कर पाना असंभव होगा। ऐसे में छात्रों का यह साल खराब होगा। जो ज्यादातर छात्र और अभिभावक नहीं चाहते है।

एनटीए के महानिदेशक विनीत जोशी ने बताया कि जहां तक बात कोरोना संक्रमण से सुरक्षा को लेकर है, तो वह सरकार की ओर से जारी सुरक्षा निदेशों का पूरी तरह से पालन करेंगे। इसकी तैयारियां भी पूरी हो चुकी है। परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ी दी गई है। वहीं नीट की परीक्षा में एक कमरे में सिर्फ 12 छात्रों को ही बैठाया जाएगा। अब तक एक कमरे में 25 छात्रों को बैठाया जाता था ।वहीं जेईई मेंस की परीक्षा जो पूरी तरह कम्प्यूटर बेस्ड होती है, उनमें भी अलग - अलग शिफ्टों में बच्चों को बुलाया गया है। साथ ही कम्प्यूटरों को नंबरिंग भी की गई है। इसके तहत एक शिफ्ट में सम नंबर वाले कम्प्यूटर पर परीक्षा होगी, जबकि दूसरी शिफ्ट में विषम नंबर वाले कम्प्यूटर पर परीक्षा होगी।

रेलवे की खाली भूमि पर 20 गीगावाट नवीन ऊर्जा उत्पादन की योजना

नई दिल्ली, प्रेट्र। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को कहा कि भारतीय रेलवे की खाली पड़ी भूमि पर 20 गीगावाट क्षमता की नवीन ऊर्जा उत्पादन की योजना है। इन संयंत्रों में देश में निर्मित सौर और पवन ऊर्जा उपकरणों का उपयोग किया जाएगा और उत्पादित बिजली का उपयोग रेलवे अपने नेटवर्क में करेगी। वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय की भी जिम्मेदारी संभालने वाले गोयल के मुताबिक आने वाले वर्षों में भारतीय रेलवे का नेटवर्क 100 प्रतिशत बिजली चालित होगा। इस लिहाज से यह दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क होगा।
गोयल ने कहा कि हमारी जो अधिशेष जमीन है, उसका बड़ा हिस्सा और ट्रैक के पास उपलब्ध भूमि का उपयोग नवीन ऊर्जा उत्पादन में किया जाएगा। भारत में बने सौर व पवन ऊर्जा उपकरणों का प्रयोग किया जहा रहा है। इन भूखंडों पर 20 गीगावाट नवीकरणीय बिजली उत्पादन करने की योजना है। यह बिजली हमारे पूरे नेटवर्क को चालाने के लिये पर्याप्त होगी। काउंसिल ऑफ एनर्जी, एनवायर्नमेंट एंड वाटर (सीईईडब्ल्यू) द्वारा स्वच्छ ऊर्जा पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि रेलवे को इस तरह की बिजली के लिए बैटरी स्टोरेज के विस्तार या बिजली संग्रह की अन्य प्रणालियों को विकसित करने की जरूरत होगी। उधर, राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) की सख्ती के बाद रेलवे प्रदूषण नियंत्रण के लिए प्रभावी कदम उठाने जा रहा है।

ग्रामीण अंचल

प्रयागराज गुरूवार, 27 अगस्त, 2020

संक्षेप समाचार

कोर्ट के फैसले पर किसानों ने जताया आभार

शंकरगढ़। मजदूर किसान मोर्चा की बैठक में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का मजदूर,किसानों ने स्वागत किया है। बता दें कि विगत दिनों शंकरगढ़,बारा क्षेत्र के किसानों और गरीब मजदूरों के ऊपर पर्यावरण विभाग द्वारा लगभग 7,25000 रुपये का जुमार्ना लगाया गया था। और कहा गया था कि यह लोग अवैध रूप से सिलिका सैंड का वाशिंग प्लांट चलाते हैं ।किसानों मजदूरों ने बताया कि यह आरोप और जुमार्ना बिना कोई ठोस सबूत के और ना किसी तथ्य व सूचना के मनमानी ढंग से एक जगह बैठक कर 61 लोगों पर लगा दिया गया ।यह जुमार्ना राशि किसी की भी देने की हैसियत नहीं है। जिस पर गरीब किसानों द्वारा तहसील दिवस, प्रदूषण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार व एनजीटी कोर्ट में अपनी गुहार लगाई। परंतु कहीं भी कोई सुनवाई और न्याय नहीं मिला।

यूरिया की कालाबाजारी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन

फूलपुर। यूरिया के आभाव में किसानों को हो रही भारी परेशानियों को देखते हुए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर जिला कांग्रेस कमेटी प्रयागराज के कांग्रेस कार्यकताओं ने बुधवार को फूलपुर तहसील का घेराव कर राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जिलाध्यक्ष रामकिशुन पटेल ने कहा की प्रदेश में पढ़ा लिखा युवक रोजगार के आभाव में बेरोजगारी का दंश तो झेल ही रहा है वहीं अपने को किसानों का हितैषी बताने वाली सूबे की सरकार किसानों को यूरिया ही नहीं उपलब्ध करवा पा रही है। कांग्रेस के पूर्व जिला उपाध्यक्ष अशफाक अहमद ने भाजपा सरकार को किसान विरोधी बताते हुए कहा की सूबे की सरकार अपने हर मुद्दे पर विफल रही है ।सबका साथ सबका विकास की बात करने वाली भाजपा की सरकार में किसान परेशान हैं ।खाद की बात हो या बढ़े विधुत दर की बात हो सरकार ने किसानों को लूटने का ही काम किया है। गरीब किसान की अपनी खेती से ही सारी उम्मीदें जुड़ी होती है। ऐसे में कालाबाजारी के चलते उन्हें खेतों में डालने के लिए यूरिया खाद नहीं मिल रही है।

यूरिया की कालाबाजारी को लेकर ज्ञापन सौंपते कांग्रेसी

धरने को सम्बोधित करतें हुए जिला प्रवक्ता डॉ अजय प्रकाश सरोज ने कहा कि किसानों को इस समय यूरिया खाद की अति आवश्यकता है वहीं सरकार के इसारे पर यूरिया की कालाबजारी करवाई जा रहीं है। उन्होंने सरकारी संरक्षण में यूरिया को सहकारी समितियों में पहुचाने के बजाए निजी दुकानों पर महंगे दामों पर विक्रय करने का आरोप लगाया। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता देवराज उपाध्याय ने कहा कि किसानों की परेशानियों को अगर नजरंदाज किया गया तो हम उनकी आवाज बनने का काम करेंगे। इस अवसर पर किसान नेता एडवोकेट शमीम अहमद , जिला महासचिव अशोक मिश्रा , जिला सचिव अजीत भारतीय, बृजेश सिंह ,दिवाकर भारतीय, सुनील यादव, दिनेश पटेल, अरविंद कुमार पासी, अशफाक अहमद, मुरारी लाल पटेल, सूरज पासी, प्रमोद पटेल, धीरेंद्र प्रकाश, मोहम्मद शाकिब, जितेंद्र सिंह, गोबिंद सिंह, प्रियांशु पटेल, तेज विश्वकर्मा, पहलवान यादवेंद्र यादव, चंद्रजीत, राजू, महेश, ओम प्रकाश यादव सहित अन्य कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित रहें।

सपाइयों ने जिलाध्यक्ष को दी बधाई

करछना। पार्टी के प्रति वफादारी व आमजन की सेवा के लिए हर पल तैयार रहने वाले योगेश यादव को सपा ने प्रयागराज का जिलाध्यक्ष बनाये जाने से पार्टी मजबूती प्रदान करेगी। जिसे लेकर बुधवार को क्षेत्र के भीरपुर मे सपा कार्यकर्ताओ की एक बैठक आहूत की गई। इस दौरान वरिष्ठ सपा नेता छोटेलाल शर्मा ने कहा कि समाजवादी पार्टी के योगेश को जुझारू कर्मठ और ईमानदार के साथ साथ पार्टी के प्रति उनकी निष्ठा से कार्यकर्ताओ का हौंसला बुलंद करेगा। इस मौके पर कई सपाई मौजूद रहे।

हाईकोर्ट समाचार

कचहरी बन्द रहते हाईकोर्ट से सीधे सोलह विदेशी जमातियों को मिली जमानत

प्रयागराज। मरकज निजामुद्दीन दिल्ली से लौटे दो अलग अलग जमातों जिसमें सात इंडोनेशियन व नौ थाईलैंड के जमातियों की जमानत उच्च न्यायालय से स्वीकार हो गयी है। ये जमानतें न्यायमूर्ती सौरभ श्याम शमशेरी ने आरोपियों के वकीलों सय्यद अहमद नसीम व मुहम्मद खालिद को सुनकर स्वीकार किया। उक्त प्रकरण में दो अलग अलग एफआईआर थाना शाहगंज में सात विदिशियों सहित 17 लोगों के विरुद्ध नामजद एफआईआर धारा 188, 269, 270, 271 आईपीसी 3 महामारी अधिनियम व 14बी, 14सी में दर्ज की गई थी। जिसमें बाद में इलाहाबाद विवि के प्रोफेसर मो शाहिद को भी 120बी का आरोपी बनाया गया था। करेली थाना के दूसरे प्रकरण में इन्ही धाराओं में 24 मार्च से ही मस्जिद हेरा में क्वारंटीन किये गए 9 थाईलैंड के जमातियों व मस्जिद इमाम उजैफा सहित सभी 30 आरोपियों को महबूबा पैलेस में क्वारंटीन करने के बाद 21 अप्रैल को महबूबा पैलेस से ही गिरफ्तारी दिखाकर चालान कर दिया गया था। सात इंडोनेशियन तब्लीगी जमात के व दो अनुवादकों को अब्दुल्ला मस्जिद मरकज में छिपाने के लिए 9 लोगों को जिम्मेदार बताया गया था। करेली प्रकरण में इमाम उजैफा व दो अनुवादकों की जमानत पूर्व में ही सत्र न्यायालय से हो चुकी है तथा अब्दुल्ला मस्जिद के 11 संरक्षण देने वालों तथा अनुवादकों की जमानत भी पूर्व में सत्र न्यायालय से स्वीकार हो चुकी है। परन्तु कोविद 19 के दिशा निर्देशानुसार जिला न्यायालय के लगातार बन्द रहने के कारण विदेशी जमातियों की जमानत प्रार्थना पत्र सत्र न्यायालय में दाखिल नहीं हो सकी थी। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय संदीप कुमार बत्रा बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र व अन्य धरम सिंह बनाम स्टेट ऑफ यूपी 2018, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था सूरज कुमार बनाम स्टेट ऑफ यूपी 2020 के साथ की जिला न्यायालय के बन्द रहते 439 दण्ड प्रक्रिया संहिता में उच्च न्यायालय में भी प्रार्थना पत्र दी जा सकती है। आरोपियों की ओर से दो प्रार्थना पत्र दाखिल की गयी। जिसमें कहा गया कि सभी आरोपियों पर संक्रमण फैलाने, वीजा का दुरुपयोग करने का आरोप है। आरोपियों की ओर से कहा गया कि जब कई बार की टेसिंटग में सभी निगेटिव पाए गए, जब स्वयं वो संक्रमित नहीं थे तो संक्रमण फैलाने का औचित्य नहीं। किसी प्रकार से वीसा के नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ। क्योंकि वीसा नियम के पैरा 15 में उल्लिखित है कि टूरिस्ट वीजा पर धार्मिक कार्यक्रमों में सम्मिलित हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि केंद्र सरकार द्वारा 2 अप्रैल को सभी डीजीपी को निर्देश जारी किया गया तथा प्रेस नोट जारी कर पूरे देश में जमातियों के विरुद्ध विभिन्न एक्ट में कार्यवाही को निर्देशित किया गया। जो साबित करता है कि अपराध होने से पहले ही अपराधी बना दिया गया। भारत सरकार की ऑफिशियल वेबसाइड पर फॉर्म सी भी जो जरुरी होती है, 24 मार्च को ही अपलोड कर दिया था तथा एलआईयू व पुलिस को सूचित भी कर दिया गया था। उनके द्वारा किसी प्रकार का कोई भी अपराध कारित नहीं किया गया है। दोनों प्रार्थना पत्रों में जमानत का पर्याप्त आधार पाते हुए थाना शाहगंज मामले में इंडोनेशिया के इदरिस उमर, अदि कुस्तीना, समसुल हादी, इमाम साफी, सतिजो जोइडिनो, हेन्द्रा सिंम्बोलन, डैडीके इसकेन्डेर व थाना करेली मामले में थाईलैंड के मोहम्मद मदाली, हसन पाचो, सिथि पोन, सुरस्क, अरसेनन, अब्दुल बसीर, अब्दुनलः, उपदान वहाब, रोमली कोली की जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ली है।

लंका थाने से बीएचयू के लापता छात्र मामले में पुलिस कार्रवाई पर कोर्ट की फटकार

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी के लंका थाने से लापता काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के छात्र शिव कुमार त्रिवेदी के बारे में पुलिसिया रवैये पर नाराजगी व्यक्त की है और कड़ी फटकार लगायी है। कोर्ट ने एसएसपी वाराणसी को तीन सितम्बर को व्यक्तिगत हलफनामे के साथ हाजिर होने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने एसएसपी से पूछा है कि 12 फरवरी को थाने में बुलाये गये छात्र के दूसरे दिन भाग जाने पर पुलिस ने क्या कार्यवाही की। पुलिस द्वारा उठाये गये कदमों का पूरा व्योरा दाखिल करने का कोर्ट ने निर्देश दिया है। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविन्द माथुर तथा न्यायमूर्ति एसडी सिंह की खंडपीठ ने अधिवक्ता सौरभ तिवारी की पत्र जनहित याचिका पर दिया है । कोर्ट ने 19 अगस्त को डीएम, एसएसपी वाराणसी व लंका थाना इंचार्ज को नोटिस जारी कर थाने से लापता छात्र की पूरी जानकारी मांगी थी। क्षेत्राधिकारी भेलूपुर ने हलफनामा दाखिल किया और कहा कि पुलिस ने आवश्यक कदम उठाये है। कोर्ट ने कहा कि 12 फरवरी को लंका थाने में बुलाने के बाद क्या हुआ, इसकी कोई जानकारी नहीं दी गयी है। अपर महाधिवक्ता ने कहा कि छात्र दूसरे दिन थाने से भाग गया। कहा गया इसकी जानकारी नहीं है। एक विक्षिप्त व्यक्ति मिला है। उसके लापता छात्र होने की आशंका है। जिसकी पहचान के लिए डीएनए बायोमैट्रिक टेस्ट कराया जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि यह समझ से परे है कि एक छात्र थाने में बुलाया गया और दूसरे दिन भाग गया। जिसका जीडी में कोई जिक्र नहीं है। तथ्यहीन हलफनामा दाखिल किया गया है।

संविदा अंग्रेजी अध्यापिका की गिरफ्तारी पर रोक

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कस्तूरबा गाँधी बालिका इंटर कालेज देवरिया में पिछले पांच साल से संविदा पर कार्यरत अंग्रेजी अध्यापिका विजया सिंह की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इन पर फर्जी दस्तावेज से नौकरी हासिल करने का आरोप लगाया गया है। याचिका में कोतवाली देवरिया में 22 जुलाई 20 को दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की गयी थी। कोर्ट ने कहा है कि याची पुलिस विवेचना में सहयोग करे और पुलिस रिपोर्ट पेश होने तक गिरफ्तारी न की जाय। यह आदेश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा तथा न्यायमूर्ति अजीत सिंह की खंडपीठ ने विजया सिंह की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता आदर्श सिंह व अजीत सिंह ने बहस की। याची का कहना है कि वह पांच सालों से प्रति वर्ष की संविदा के आधार पर अंग्रेजी अध्यापिका पद पर कार्यरत हैं। उसका नवीनीकरण 15 जुलाई 20 को होना था। सेवाकाल में उसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं है। दुर्भाग्यवश उस पर फर्जी दस्तावेज से नौकरी हासिल करने का आरोप लगाया गया है। जबकि इन्हीं दस्तावेजों पर हर साल संविदा नवीनीकरण होता रहा है। आरोप निराधार व मनगढ़ंत है।

हाईकोर्ट बार सम्पत्ति क्षति दावा अधिकरण को लेकर मुख्यमंत्री व कानून मंत्री से मुलाकात कर रखेगा पक्ष

प्रयागराज। सम्पत्ति क्षति दावा अधिकरण की पीठें लखनऊ और मेरठ में बनाने के लिए पारित विधेयक के विरोध को हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जन आंदोलन का रूप देगा। इसके लिए बुधवार को हुई पूर्व पदाधिकारियों के साथ बैठक में रणनीति पर चर्चा की गई। विधेयक को निरस्त कराने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर भी चर्चा हुई।

बैठक में कहा गया कि अधिकरण आम जनमानस पर बोझ है और सरकार द्वारा उठाया गया कदम निरर्थक है। बैठक में तय किया गया कि बार एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री, राज्य विधिमंत्री और प्रमुख सचिव न्याय से मिलकर इस मामले पर अपना पक्ष रखेगा। यदि शासन द्वारा इसकी अनदेखी की जाती है तो इसे जनआंदोलन का रूप दिया जाएगा। बैठक में शामिल पूर्व पदाधिकारियों का सुझाव था कि आंदोलन से व्यापारियों, छात्रों, कर्मचारी संघों सभी बार एसोसिएशनों को भी जोड़ा जाएगा तथा इसे प्रयागराज की आम जनता तक ले जाया जाएगा तथा सरकार के विरुद्ध धरना प्रदर्शन किया जाएगा। यह भी निर्णय लिया गया कि एक जनहित याचिका दाखिल कर कानूनी रूप से लड़ाई लड़ी जाएगी।

बैठक में बार के महासचिव प्रभाशंकर मिश्र ने कहा कि सरकार द्वारा उठाया गया कदम निंदनीय है। क्योंकि इससे सिर्फ अधिवक्ता ही नहीं प्रयागराज के सभी वर्गों को नुकसान होगा। अगली बैठक पूर्व और वर्तमान पदाधिकारियों की एक साथ होगी जिसमें लिए गए निर्णय के अनुसार आंदोलन किया जाएगा। बैठक में पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता वीपी श्रीवास्तव, पूर्व अध्यक्ष आईके चतुर्वेदी, पूर्व महासचिव सीपी उपाध्याय, पूर्व महासचिव ओपी सिंह, पूर्व महासचिव रामशिरोमणि शुक्ला, पूर्व महासचिव जेबी सिंह, अशोक कुमार सिंह, एके ओझा, एससी उपाध्याय सहित अन्य अधिवक्ता उपस्थित थे। सभा का संचालन महासचिव प्रभाशंकर मिश्र ने किया।

गोवंशों ने मचाया आतंक, किसान परेशान

कौंधियारा। विकासखंड के 57 ग्राम पंचायतों में से टिकरी, जोकनई, कुल्हड़िया, नौगांवा, देवरा, पवरी सहित 6 ग्राम पंचायतों में गौ आश्रय स्थल का निर्माण कराया गया है लेकिन खंड विकास अधिकारी कार्यालय कौंधियारा के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की लापरवाही के कारण आऐ दिन गौ आश्रय स्थल के टैग लगे पशु गांवो में धावा बोल देते हैं जिससे क्षेत्र के टिकरी, बरसवल, नचना, खजूरी, जोकनई, लहबरा आदि गांव में फसलों को गोवंशो द्वारा भारी नुकसान पहुंचाया जाता है सोमवार को लहबरा गांव के प्रमोद पांडे, अंकित पांडे, अमरनाथ हरिजन, अवधेश सिंह, बबलू पांडे एवं मयंक पांडे सहित दर्जनों की संख्या में किसानों ने लगभग तीन दर्जन आवारा टैग लगे गौआश्रय के गौवशों को गांव के बगीचे में बांध दिया गौ वशों के बांधने की सूचना उप जिलाधिकारी करछना आकांक्षा राणा व खंड विकास अधिकारी कौधियारा नवीन गुप्ता को दी गई ।

पेड़ों से बंधे गोवंश

मण्डल स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक सम्पन्न

प्रयागराज। मण्डलायुक्त आर0 रमेश कुमार की अध्यक्षता में गांधी सभागार में बुधवार को मण्डल स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गयी। बैठक में मण्डलायुक्त ने मुख्य मार्गों पर चिन्हित ब्लैक स्पाट स्थानों पर आवश्यकतानुसार स्पीड ब्रेकर बनाये जाने एवं संकेतक बोर्ड लगाये जाने का निर्देश दिया है। उन्होंने ये भी निर्देशित किया कि किसी स्थान पर यदि एक से अधिक बार दुर्घटना होती है तो वहां पर सड़क सुरक्षा समिति से सम्बंधित अधिकारीगण भ्रमण कर दुर्घटना के कारणों के बारे में अध्ययन करते हुए उस स्थान पर दुर्घटना को रोकने के सम्बंध में आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए कहा है। उन्होंने राजमार्गों पर दस-दस किलो मीटर के अंतराल पर हेल्प लाइन नम्बर, कितनी दूरी पर पेट्रोल पम्प स्थित है तथा अन्य आवश्यक जानकारियों से सम्बंधित बोर्ड लगाये जाने का निर्देश दिया है। मण्डलायुक्त ने अभियान चलाकर अनधिकृत रूप से चलने वाले वाहनों एवं ओवरलोड वाहनों के विरूद्ध चेकिंग की कार्रवाई किये जाने का निर्देश दिया है। उन्होंने ओवरलोडिंग में क्रेसर मालिको सहित अन्य सम्बंधित लोगो के विरूद्ध भी कार्रवाई किये जाने का निर्देश दिया है। बैठक में मुख्य मार्गों तथा राजमार्गों से मिलने वाले लिंक मार्गों पर होने वाली दुर्घटनाओं को रोके जाने के बारे में भी पीडब्लूडी तथा एनएचआई को आवश्यक कार्रवाई किये जाने का निर्देश दिया गया है। कहा गया कि लिंक मार्गों को इस तरह से बनाया जाये कि मुख्य मार्गों से उनका संपर्क सीधे न होकर घुमावदार ढंग से किया जाये तथा ऐसे स्थानों पर संकेतक भी लगाये जाये।

बैठक में उपस्थित अधिकारी व अध्यक्षता करते मण्डलायुक्त

मण्डलायुक्त ने स्कूलों के खुलने पर स्कूली वाहनों के लिए निर्धारित किए गये मानकों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने का निर्देश दिया है। बैठक में यह भी कहा गया कि किसी भी दशा में एलपीजी से स्कूली वाहन न चलने पाये। मण्डलायुक्त ने स्कूलों के खुलने से पहले ही स्कूल प्रबंधकों, पैरेंट्स तथा अन्य सम्बंधित लोगो के साथ कार्यशाला आयोजित कर सुरक्षा के मानको के बारे में प्रशिक्षित कराये जाने का निर्देश परिवहन विभाग को दिया है। मण्डलायुक्त ने शहर में डीजल से चलने वाले ऑटो के विरूद्ध अभियान चलाकर ऐसे वाहनों को रोके जाने का निर्देश दिया है। नये यमुना पुल के पास अधिक मात्रा में बस तथा ऑटो खड़े होने के कारण आवागमन में होने वाले व्यवधान की समस्या का निस्तारण किए जाने का भी निर्देश दिया है।

बैठक में पुलिस महानिरीक्षक श्री के0पी0 सिंह ने कहा कि लापरवाही पूर्वक या नशा करके वाहन चलाने वाले चालकों के विरूद्ध चेकिंग की कार्रवाई कर दोषी पाये जाने पर ऐसे वाहन चालको का लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाये। उन्होंने कहा कि दुर्घटना के कारणों के बारे में भी अध्ययन किया जाना चाहिए कि किस कारण से या किसकी गलती से दुर्घटना घटी, जिससे कि ऐसे लोगो के विरूद्ध भी कार्रवाई हो सके। उन्होंने ब्लैक स्पॉट स्थानों के नजदीक एम्बुलेंस की भी व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के लिए कहा, जिससे कि दुर्घटना घटित होने पर तत्काल पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाकर उनका उपचार समय से किया जा सके। शहर में चलने वाले टैम्पों तथा ई-रिक्शा को निरंतर सैनेटाइज कराये जाने के लिए भी कहा गया है। इस अवसर पर अपर आयुक्त भगवान शरण, अपर निदेशक स्वास्थ्य, एसपी टैªफिक, सम्भागीय परिवहन अधिकारी, पीडब्लूडी सहित अन्य सम्बंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे।

बिजली विभाग की लापरवाही से हो रही है योगी सरकार बदनाम

लालापुर। लालापुर क्षेत्र के मानपुर गांव में कई ग्रामीणों ने सौभाग्य योजना के तहत 2018 से ही कनेक्शन ले रखा है जिसका बिजली विभाग द्वारा बिलिंग भी किया जा रहा है परंतु आज तक ना ही पोल लगे ना ही बिजली के तार उपभोक्ताओं को कनेक्शन दिया गया और मात्र मीटर लगाकर सेलिंग बुक कटवा कर अवैध वसूली हो रही है जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने कई बार बिजली विभाग के जेई, एसडीओ, एक्ससियन वा एसी को किया गया उसके बावजूद बिजली विभाग के अधिकारियों को कोई फर्क नहीं पड़ा बिजली विभाग के लापरवाही से आजिज होकर ग्रामीणों की समस्या को देखते हुए भाजपा जिला सूचना प्रमुख अनुज सिंह परिहार ने भी कई बार विभाग के आला अधिकारियों को इस बात की जानकारी दी इसके बावजुद भी आज तक नही हुई कोई कार्यवाही।

दो दिवसीय सामूहिक देशव्यापी हड़ताल पर रहेंगे मनरेगा कर्मचारी

जसरा । अखिल भारतीय मनरेगा कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर पूरे देश के मनरेगा कर्मचारी झारखंड के कर्मचारियों के समर्थन में 2 दिन की सामूहिक देशव्यापी हड़ताल का निर्णय लिया है। मनरेगा के ब्लॉक अध्यक्ष ने बीडीओ जसरा को आठ सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। विकासखंड जसरा में मनरेगा के कर्मचारियों ने जसरा विकास खंड अधिकारी को एक पत्र सौंप करके बताया कि झारखंड के मनरेगा कर्मचारियों के अनिश्चित काल हड़ताल के समर्थन में पूरे देश में मनरेगा कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे दो दिवसीय हड़ताल में जसरा के कर्मचारी पूरी तरह से हड़ताल में सम्मिलित रहेंगे।

कर्मचारियों ने बताया कि झारखंड सरकार के साथ पूरे देश के मनरेगा कर्मियों ने कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी के समय बिना किसी सुरक्षा के अपने जीवन को दांव पर लगा करके निरंतर गांव के श्रमिकों एवं प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराए जाने के कार्य में जुड़े रहे। जिसके चलते कई मनरेगा कर्मचारी कोरोना की चपेट में भी आए हैं` ऐसे समय में जब मनरेगा के कर्मचारियों को ध्यान में रखते हुए उनके सेवा व मानदेय बढ़ाए जाने की जरूरत है तो ऐसे समय में सरकार जिस तरह से झारखंड के मनरेगा कर्मियों की सेवा समाप्ति की धमकी दे रही हैं उससे पूरे देश के मनरेगा कर्मचारियों में घोर रोष व्याप्त है ` कर्मचारियों ने अपने मांग पत्र में कहा कि वर्षों से संविदा पर काम कर रहे कर्मचारियों को सरकारी सेवक घोषित

बीडीओ जसरा को ज्ञापन सौंपते हुए

किया जाए तथा उससे संबंधित समकक्ष पदों पर इनको समायोजित किया जाए तथा मानदेय के बजाय इनके वेतन कोष का गठन करके प्रतिमाह वेतन का भुगतान किया जाए। पूरे देश के मनरेगा कर्मियों को उनके पद के अनुसार एक समान वेतन भी दिया जाए` अभी भी अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग मानदेय निर्धारित है ` जबकि सभी मनरेगा कर्मचारी मनरेगा एक्ट में निहित प्रावधानों के अंतर्गत ही कार्य कर रहे हैं ` तथा मनरेगा कर्मियों की सेवा पुस्तिका बनाए जाने का भी आदेश दिया जाए । इसी तरह कई मांगों से संबंधित मांग पत्र आज मनरेगा कर्मी कार्मिक संघ जसरा अपने अध्यक्ष संदीप कुमार के साथ खंड विकास अधिकारी जसरा देवेन्द्र कुमार ओझा को आठ सूत्रीय मांग पत्र सौंपा` इस मौके पर मुख्य रूप से तारा सिंह, विभव नाथ, ज्ञानेश्वर पांडे, सहित कई दर्जनों मनरेगा कर्मी उपस्थित रहे।

सपा नेताओं ने मेधावियों को भेंट किया लैपटॉप, दी शुभकामनाएं

प्रयागराज। जनपद के मेधावी छात्र-छात्राओं को सपा जिलाध्यक्ष योगेश यादव, एमएलसी बासुदेव यादव एवं रामबृक्ष यादव ने बुधवार को लैपटॉप भेंट कर सम्मानित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से मेधावियों और उनके माता पिता को शुभकामनाएं दी।

एमएलसी बासुदेव यादव ने इस मौके पर कहा कि समाजवादी पार्टी की पूर्ववर्ती सरकारों में प्रदेश में शिक्षा और रोजगार के लिए अभूतपूर्व कार्य हुए जो अन्य प्रदेशों के लिए नजीर बन गए हैं। पिछली सरकार में छात्र-छात्राओं को 18 लाख लैपटॉप देकर कीर्तिमान स्थापित किया गया है। एमएलसी रामबृक्ष यादव ने कहा कि भाजपा की केंद्र एवं प्रदेश सरकार ने समाज में भेदभाव, सांप्रदायिक सौहार्द को तोड़ने, खासकर उत्तर प्रदेश में

मेधावी नमन को लैपटॉप देते सपा नता

विकास के नाम पर सपा की पिछली सरकार में किए गए कार्यों का उद्घाटन कर वाहवाही लूट रही है। सपा जिलाध्यक्ष योगेश यादव ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से मेधावियों और उनके माता पिता, गुरुजनों को शुभकामना देते हुए बधाई दी और कहा कि आगे भी इसी तरह से जनपद का नाम रोशन करे।

सपा के जिला प्रवक्ता दान बहादुर मधुर के अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा प्रदेश भर में मेधावियों को लैपटॉप दिया जा रहा है। प्रयागराज जिले में कुल सात छात्र-छात्राओं को चिन्हित किया गया है। इसी क्रम में आज यूपी बोर्ड की हाईस्कूल परीक्षा में प्रदेश में आठवां और जिले में पहला स्थान पाने वाले बहादुरपुर ब्लाक के ग्राम मुरादपट्टी के नमन यादव पुत्र करतार सिंह एवं बजहा के मेधावी छात्र मुकेश कुमार पुत्र रामलाल को उनके घर जाकर लैपटॉप भेंट किया गया। इस मौके पर पूर्व जिलाध्यक्ष कृष्णमूर्ति सिंह, डॉ मानसिंह यादव, जिला महासचिव संदीप सिंह पटेल, उपाध्यक्षगण राम सुमेर पाल, अनिल कुमार यादव, महावीर यादव, डॉ एसपी सिंह पटेल, दूधनाथ पटेल, आरएन यादव, राकेश सिंह, अचल यादव आदि मौजूद रहे।

उत्तर प्रदेश में पत्रकारों की हत्या गम्भीर विषय ध्यान दे सरकार : आलोक त्रिपाठी

घूरपुर। भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ ने उत्तर प्रदेश में पत्रकारों की आए दिन हो रही हत्या पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री से इस संदर्भ में तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की है और कहा है कि सूबे के मुखिया होने के नाते उनका नैतिक दायित्व है कि कलम के सिपाहियों को सुरक्षा प्रदान करें। भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के मंडल अध्यक्ष प्रयागराज आलोक त्रिपाठी ने कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश कलम के सिपाहियों की सुरक्षा के लिए प्रदेश में तत्काल पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की पहल करें। और आए दिन हो रही पत्रकारों की हत्या जो कि एक गंभीर विषय है इस पर वे अविलंब रोक लगाने का सार्थक प्रयास करें ।पत्रकारों के आए दिन हो रहे उत्पीड़न पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए पत्रकार उन्होंने कहा है कि प्रदेश का शासन और प्रशासन कलम कारों की सुरक्षा करने में नाकाम साबित हो रहा है और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में अनादर किया जा रहा है वह कतई उचित नहीं है ।इस संदर्भ में प्रदेश के मुखिया को चाहिए कि वे अभिलंब उच्चस्तरीय जांच कराकर सभी मामलों में पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने की पहल करें ।और अभी तक जिन पत्रकारों की हत्या की गई है उनके परिवारों को न्यूनतम 50लाख का मुआवजा देकर उनके भरण-पोषण की व्यवस्था बनाएं। परिवार को सुरक्षा प्रदान करने के लिए उन्हें आवश्यकतानुसार शस्त्र लाइसेंस आदि भी प्रदान करें। इसी तरह पूरे प्रदेश में हो रहे पत्रकार उत्पीड़न को रोकने के लिए पत्रकार सुरक्षा कानून बनाना अब अनिवार्य हो गया है ।प्रदेश सरकार को इस पर तत्काल अमल करना चाहिए ।महासंघ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में माफियाओं के साथ साथ पुलिस द्वारा भी आए दिन पत्रकारों का उत्पीड़न होता रहता है जबकि उच्च स्तरीय अधिकारी बार-बार आपसी सद्भाव और तालमेल बनाने की बात करते हैं ।

प्रयागराज हलचल

संक्षेप समाचार

अवैध बालू लदे मैजिक को पुलिस ने पकड़ किया सीज

घूरपुर। घूरपुर पुलिस टीम ने बुधवार के दिन वाहन चेकिंग के दौरान एक अवैध बालू लदे मैजिक को चालक समेत पकड़ लिया ।बालू लदे मैजिक को सीज करने के बाद चालक को जेल भेज दिया गया । घूरपुर एसओ भुवनेश चौबे बुधवार के दिन वाहनों की जांच कर रहे थे ।इसी बीच अवैध बालू लादकर एक मैजिक निकली जिसे पुलिस ने रोक लिया और बालू परिवहन करने का प्रपत्र मांगा तो चालक नही दिखा पाया ।मैजिक समेत चालक को पुलिस थाने ले गई ।जहां मैजिक को सीज कर दिया गया और चालक लवकुश बिंद निवासी बड़गोहना थाना कौंधियारा को जेल भेज दिया गया ।

माफिया अतीक के सम्पत्तियों की हुई कुर्की

प्रयागराज। पूर्व सांसद माफिया अतीक अहमद की सम्पत्तियों की कुर्की बुधवार सुबह भारी पुलिस बल के साथ शुरू कर दी गई। आज सात चिन्हित सम्पत्तियों की कुर्की होने की जानकारी मिली रही है। उक्त कार्रवाई शासनादेश की मन्सानुसार जिलाधिकारी के निर्देश पर की जा रही है।

धूमनगंज थाने की पुलिस ने क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय अजीत सिंह के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक धूमनगंज, प्रभारी निरीक्षक सिविल लाइंस भारी पुलिस बल के साथ राजरूपपुर स्थित फ्लैट और मकान पर पहुंचे और कुर्की की कार्रवाई शुरू कर दी है।

इसी तरह सिविल लाइंस में महत्मा गांधी मार्ग स्थित बिल्डिंग एवं दुकान में कुर्की कार्रवाई पुलिस ने शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि खुल्दाबाद के चकिया में स्थित मकान और कर्बला स्थित कार्यालय समेत सात अंचल सम्पत्तियां सामिल है।

अतीक अहमद के घर के बाहर तैनात पुलिस

गौरतलब है कि तेरह दिन पूर्व जिलाधिकारी भानुचन्द्र गोस्वामी ने गैगेस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई का निर्देश दिया था।जिसकी रिपोर्ट 28अगस्त देना था। मंगलवार को नगर निगम और प्रयागराज विकास प्राधिकरण की संयुक्त टीम ने पुलिस के साथ स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अतीक की कुल 37 अंचल सम्पत्तियां चिन्हित की गई। जिसमें कई मकान, खाली प्लाट एवं खेत भी है।

उल्लेखनीय है कि पूर्व सांसद माफिया अतीक गुजरात के अहमदाबाद जेल में बंद हैं। उनके भाई पूर्व विधायक अशरफ समेत कई करीबी जेल में हैं।

सहायक अध्यापक भर्ती में नियुक्ति का मानक अलग क्यों : हाईकोर्ट

बेसिक शिक्षा निदेशक को व्यक्तिगत हलफनामा देने का निर्देश

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा निदेशक उ प्र से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है तथा पूछा है कि प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति का मापदंड विभिन्न जिलों में अलग अलग क्यों है ? जम्मू-कश्मीर विश्वविद्यालय से एलिमेन्ट्री टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स डिप्लोमा धारकों को कुछ जिलों में वैध मानते हुए नियुक्ति की गयी है और शामली बीएसए ने डिप्लोमा को अमान्य कर नियुक्ति देने से इंकार कर दिया है। जिसे चुनौती दी गयी है। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने शामली की श्रीमती शालू शर्मा व अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता राघवेन्द्र प्रसाद मिश्र ने बहस की। याची का कहना है कि 68500 सहायक अध्यापक भर्ती में शामिल याचियों की काउन्सिलिंग की गयी किन्तु नियुक्ति नहीं की गयी। हाईकोर्ट ने बीएसए शामली को निर्णय लेने का निर्देश दिया तो उन्होंने यह कहते हुए नियुक्ति देने से इंकार कर दिया कि जम्मू-कश्मीर में एनसीटीई के नियम लागू नहीं होते। जिसे चुनौती दी गयी है। याची का कहना है कि अब जम्मू-कश्मीर में भी एनसीटीई के नियम लागू है। ऐसे डिप्लोमा धारकों को कुछ जिलों में वैध मानते हुए नियुक्ति की गयी है और वे कार्यरत हैं। कोर्ट ने जवाब मांगा तो बीएसए शामली ने हलफनामा दाखिल किया। उन्हें ऐसे डिप्लोमा धारकों की नियुक्ति की जानकारी ही नहीं है। कोर्ट ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि एक ही भर्ती में भिन्न भिन्न जिलों में नियुक्ति प्रक्रिया भिन्न कैसे है। इस पर बेसिक शिक्षा निदेशक से व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है। याचिका की अगली सुनवाई 3 सितम्बर को होगी। कोर्ट ने कहा है यदि हलफनामा दाखिल नहीं हुआ तो कोर्ट निदेशक को तलब करेगी।

कोरोना से डॉक्टर समेत पांच की मौत, एक दिन में 368 कोरोना संक्रमित मिले

प्रयागराज। जिले में बुधवार को पांच कोरोना संक्रमितों ने दम तोड़ दिया। इनमें मांडा सीएचसी के एक डॉक्टर भी शामिल हैं। चार लोग जिले के रहने वाले थे, जबकि एक मृत महिला कौशाम्बी की थी। अस्पताल में कई और संक्रमितों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है।

सीएमओ डॉ. जीएस बापजेई ने बताया कि मांडा सीएचसी में तैनात 45 वर्षीय एक चिकित्सक कोरोना पॉजिटिव थे। वह पत्नी और बच्चे के साथ शहर स्थित राजापुर मोहल्ले में रहते थे। संक्रमित होने पर उन्हें बेली अस्पताल में भर्ती किया गया था। मंगलवार रात हालत गंभीर होने पर उन्हें एसआरएन के लिए रेफर किया गया। वहां से मेदांता भेजा गया।

सीएमओ ने बताया कि वहां उनकी मृत्यु हो गई।

इसी तरह अस्पताल के कोरोना नोडल डॉ. सुजीत कुमार वर्मा ने बताया कि सोरांव इलाके का रहने वाला 65 वर्षीय बुजुर्ग 22 अगस्त को कोरोना पॉजिटिव आया था। उसे अस्पताल में भर्ती किया गया था। सुगर के साथ बीपी की शिकायत थी। रात में 12 बजे उसने दम तोड़ दिया। इसी तरह करछना निवासी 65 वर्षीय व्यक्ति 23 अगस्त को कोरोना पॉजिटिव आने के बाद एसआरएन अस्पताल में भर्ती किया गया था। बीपी के साथ उसे निमोनिया हुआ था। दिन में साढ़े 11 बजे संक्रमित की मौत हो गई। इसी तरह, करेली निवासी 64 वर्षीय बुजुर्ग रात में भर्ती हुआ था। बीपी के साथ लकवा की शिकायत थी। बुधवार दिन में ढाई बजे उसने दम तोड़ दिया।

वहीं, एसआरएन अस्पताल में कौशाम्बी की भी एक बुजुर्ग संक्रमित महिला की मौत हो गई। वह सरायअकिल की रहने वाली थी। 75 वर्षीय महिला 24 अगस्त को अस्पताल में भर्ती की गई थी। बुधवार को दिन में तीन बजे उसने दम तोड़ दिया।

जिले में बुधवार को एक दिन में सबसे अधिक 368 कोरोना संक्रमित मिले। इनमें दूसरे जनपद में तैनात यहां के एक कानूनगो, बेली अस्पताल के एक इमरजेंसी मेडिकल अफसर, सीडीए पेंशन के ऑडिटर, बैंक मैनेजर और एक सांसद का ड्राइवर शामिल है। इस तरह अब जिले में संक्रमितों की संख्या आठ हजार के पार पहुंच गई है।

कोविड 19 के नोडल डा. ऋषि सहाय ने बताया कि संक्रमित मिले लोगों में सबसे अधिक एंटीजेन जांच में पॉजिटिव आए हैं। कुल 309 लोग पॉजिटिव आए हैं। इसके आवा 40 लोग आरटीपीसीआर एवं 19 लोग ट्रूनॉट से हुई जांच में संक्रमित मिले हैं।रेलवे के एक सहायक लोको पायलट, सीआरपीएफ जवान एवं तीन वकील संक्रमित हैं। बीओबी के बैंक मैनेजर, इंश्योरेंस कंपनी के दो कर्मचारी, एचडीएफसी बैंक के एक कर्मचारी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव है। बिग बाजार का एक कर्मचारी भी संक्रमण की चपेट में है। नैनी सेंट्रल जेल के 36 सिपाही, आरएफ के तीन सिपाही व प्राइमरी के शिक्षक की रिपोर्ट पॉजिटिव है। एनटीपीसी के 17 संक्रमण की चपेट में हैं। एसबीआई के सीनियर असिस्टेंट, आरटीओ कार्यालय का सिपाही एवं साफ्टवेयर इंजीनियर की रिपोर्ट पॉजिटिव है। सीडीए पेंशन के ऑडिटर, मांडा के बीसीपीएम संक्रमित हैं। आंगनबाड़ी कार्यकत्री के साथ एक एक दंत चिकित्सक की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है।

पीसीएस 2019 मेंस का कार्यक्रम घोषित

प्रयागराज। लोक सेवा आयोग ने पीसीएस मेंस 2019 का परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। यह परीक्षा 22 से 26 सितंबर तक प्रयागराज, लखनऊ और गाजियाबाद में आयोजित की जाएगी। परीक्षा दो पालियों में होगी। पहली पाली की परीक्षा 9:30 बजे से शुरू कर 12:30 बजे तक चलेगी जबकि दूसरी पाली की परीक्षा 2 से 5 तक होगी। आयोग के सचिव जगदीश ने बताया कि 22 सितंबर को पहली पाली में अनिवार्य विषय सामान्य हिंदी और दूसरी पाली में निबंध का पेपर होगा। 23 सितंबर को पहली पाली में सामान्य अध्ययन प्रथम और दूसरी पाली में सामान्य अध्ययन द्वितीय प्रश्न पत्र की परीक्षा होगी। 24 सितंबर को पहली पाली में सामान्य अध्ययन तृतीय और दूसरी पाली में सामान्य अध्ययन चतुर्थ प्रश्न पत्र की परीक्षा होगी। एक दिन के गैप के बाद 26 सितंबर को पहली पाली में ऐच्छिक विषय के पहले और दूसरी पाली में दूसरे प्रश्न पत्र की परीक्षा होगी।

इविवि के दर्जनों छात्र एवं नेताओं ने ली एनएसयूआई की सदस्यता

प्रयागराज। प्रदेश अध्यक्ष एवं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के निवर्तमान उपाध्यक्ष अखिलेश यादव की उपस्थिति में विश्वविद्यालय में अविरल हो रहे छात्र हित कार्यों को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न छात्रों ने ठरवक की सदस्यता ग्रहण की एवं छात्रसंघ के आदर्श रहे शहीद लाल पद्मधर की प्रतिमा पर छात्रों के सेवार्थ एवं हितार्थ स्वयं का संपूर्ण देने के लिए शपथ ली। साथ ही पूरे प्रदेश में हो रहे राजीव गांधी सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता के पोस्टर का अनावरण किया एवं ज्यादा से ज्यादा छात्र छात्राओं को प्रतिभाग करने के लिए लोगों को उत्साहित किया।

मंत्री ने 47 सड़कों के निर्माण कार्यों का किया लोकार्पण

प्रयागराज। मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बुधवार को सर्किट हाउस में शहर पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र में विधायक निधि, पूर्वांचल विकास निधि व त्वरित आर्थिक विकास योजना के तहत 641.47 लाख रुपए की लागत से बनायी गयी 47 सड़कों व इंटरलाकिंग के कार्यों का लोकार्पण किया।

उन्होंने विधायक निधि योजना के अन्तर्गत कराये गये प्रमुख कार्यों में न्याय विहार कालोनी में धर्मेन्द्र प्रताप सिंह के मकान से संगम लाल के मकान तक इंटरलाकिंग कार्य, बिरजू के घर से राजीव गुप्ता के घर से होते हुए एसएन शुक्ला के घर तक सीसी मार्ग का निर्माण कार्य, देवघाट झलवा में काली माई धाम तक इंटरलाकिंग व नाली निर्माण, न्यायनगर होलिका चैराहा से समुंदर सिंह यादव के घर तक लेपन एवं इंटरलाकिंग का कार्य कराया गया। इस तरह से विधायक निधि के अन्तर्गत 207.29 लाख रुपए की लागत से 23 सड़कों का निर्माण कार्य कराया गया।

इसी प्रकार पूर्वांचल विकास निधि के अन्तर्गत हर-हर महादेव मंदिर के बगल मेन रोड से दिनेश सिंह के घर होते हुए विनोद सिंह के घर तक इंटरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य, मनौरी में राधे गेस्ट हाउस से अजय कुमार तिवारी के घर तक इंटरलाकिंग का कार्य कराया गया। पूर्वांचल विकास निधि से 47.93 लाख रुपए की लागत से छह सड़कों का निर्माण कार्य कराया गया।

त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत सैदरपुर गांव में ट्रांसफार्मर चैराहे से बरखण्डी महोदव मंदिर तक इंटरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य, ग्राम डाही में रावतपुर डामर रोड से खेड़ुआ डामर रोड तक लेपन स्तर का कार्य, पूर्व माध्यमिक विद्यालय तियरा में खटागी तियरा तक लेपन कार्य, काठ गांव में पक्की सड़क से राम बहोरे पाल के घर तक इंटरलाकिंग व नाली निर्माण कराया गया है। इस योजना के अन्तर्गत कुल 386.25 लाख रुपए की लागत से 18 सड़कों का निर्माण कार्य कराया गया।

सड़कों के निर्माण कार्यों का लोकार्पण करते मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह

तीनों योजनाओं के माध्यम से कुल 47 सड़कों का निर्माण कार्य कुल 641.47 लाख रुपए के कार्य मंत्री श्री सिंह द्वारा कराये गये। इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री के मंशानुरूप कोविड-19 महामारी के फैलने के बावजूद विकास की गति को रूकने नहीं दिया गया है। इसका प्रमाण शहर पश्चिमी में कराये गये ये निर्माण कार्य हैं। इसके उपरान्त श्री सिंह ने दिव्यांग जगमल को बैसाखी अपने हाथों से भेंट की साथ ही शहर पश्चिमी के पट्टा वितरण का कार्य भी किया।

शास्त्री पुल के पिलर नंबर 27 की बेयरिंग बैठी

प्रयागराज। शास्त्री पुल पर फिर प्रयागराज-वाराणसी लेन पर आवागमन बंद कर दिया गया है। बुधवार शाम पिलर नंबर 27 की बेयरिंग बैठने के बाद अधिकारियों ने पुल पर वनवे व्यवस्था लागू करा दी। यहां यातायात पुलिस कर्मियों को भी तैनात कर दिया गया है, ताकि जाम की स्थिति न उत्पन्न हो।

बुधवार शाम शास्त्री पुल का पिलर नंबर 27 अचानक थोड़ा नीचे खिसकने की जानकारी अधिकारियों को हुई तो तत्काल आवागमन बंद कराते हुए निरीक्षण किया। फिर दो दिन तक आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित करने की बात कही। शास्त्री पुल की देखरेख करने वाले अधिकारी अजय गोयल का कहना है कि पिलर नंबर 27 की बेयरिंग खराब होने से ऐसा हुआ है। ओवरलोड वाहनों के कारण ही अक्सर बेयरिंग खराब हो रही है। गुरुवार और शुक्रवार को यहां मरम्मतीकरण का कार्य होगा और शनिवार से यातायात बहाल किया जाएगा। इसके चलते पुल पर आवागमन वन वे कर दिया गया है। इससे पुल पर जाम की स्थिति बन गई है।

बता दें कि अभी करीब दो माह पहले भी पिलर नंबर 40 ही बेयरिंग में गड़बड़ी आ गई थी जिसके कारण यातायात बाधित हुआ था। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि पुल की मरम्?मत के लिए कानपुर से टीम को बुलाया गया है। कल से मरम्मत का काम शुरू कर दिया जाएगा।

बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के नहीं मिलेगा स्वस्थता प्रमाण पत्र

प्रयागराज। एक अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत एवं संचालित 7500 किग्रा सकल यान भार से अधिक भार क्षमता वाले समस्त माल वाहनों के स्वामी तीन माह के अन्दर अपने वाहनों पर तीसरे रजिस्ट्रेशन चिन्ह सहित हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट वाहन निमार्ता के डीलर के माध्यम से प्रतिस्थापित करना सुनिश्चित करें। उक्त जानकारी सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) सियाराम वर्मा ने बुधवार को देते हुए बताया है कि पुराने वाहनों में ह्यह्यतीसरे रजिस्ट्रेशन चिन्ह सहित अति सुरक्षा पंजीयन प्लेटह्यह्य लगाने के सम्बन्ध में परिवहन आयुक्त उ.प्र लखनऊ द्वारा दिशा-निर्देश निर्गत किये गये थे। जिसके द्वारा व्यावसायिक वाहनों पर तीसरे पंजीयन चिन्ह सहित हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट प्रतिस्थापित करने के सम्बन्ध में विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि एक अप्रैल 2019 के पूर्व से पंजीकृत एवं संचालित वाहनों के स्वामी नियत तिथि 15 अक्टूबर के पश्चात स्वस्थता प्रमाण पत्र प्राप्त करते समय अपने वाहन पर तीसरे रजिस्ट्रेशन चिन्ह सहित हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट वाहन निमार्ता के डीलर के माध्यम से प्रतिस्थापित कराना सुनिश्चित करें। श्री वर्मा ने यह भी बताया कि इस तिथि के पश्चात बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट प्रतिस्थापित हुए स्वस्थता प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किये जायेंगे। ऐसे वाहन फिटनेस प्रमाण पत्र 15 अक्टूबर के बाद (एचएसआरपी) एवं तीसरे पंजीयन चिन्ह के लगाये बिना जारी नहीं किया जाएगा।

सीएए-एनआरसी विरोध के दौरान हिंसा भड़काने व देश विरोधी बयान के आरोपी की जमानत खारिज

प्रयागराज। सीएए-एनआरसी के विरोध प्रदर्शन के दौरान लोगों को हिंसा के लिए भड़काने, सरकार और देश विरोधी बयान देने, दो समुदायों के बीच घृणा पैदा करने की कोशिश और एक धर्म विशेष के बारे में असम्मानित टिप्पणियां करने के आरोप में आजमगढ़ के ओसामा की जमानत इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नामंजूर कर दी है। जमानत अर्जी पर न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने सुनवाई की।

आरोपी ओसामा के खिलाफ आजमगढ़ के बिलरियागंज थाने में सार्वजनिक सम्पत्ति को क्षति पहुंचाने, पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला करने, देश विरोधी बयान देने सहित दर्जन भर से ज्यादा गम्भीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है। याची के अधिवक्ता का कहना था कि सभी आरोप सामान्य प्रकृति के हैं। इस मामले में आरोपी बनाए गए अन्य लोगों की जमानतें इस अदालत द्वारा पूर्व में मंजूर की जा चुकी हैं। मामले के सभी गवाह पुलिस के ही कर्मचारी हैं जिन्होंने खुद अपना बयान रिकार्ड करवाया है।

जमानत अर्जी का विरोध कर रहे सरकारी वकील का कहना था कि आरोपी का कृत्य अत्यंत गंभीर प्रकृति का है। यह सिर्फ भीड़ हिंसा को भड़काने का मामला नहीं है बल्कि दो समुदायों के बीच धर्म के आधार पर शत्रुता बढ़ाने की कोशिश की गई है। कोर्ट ने प्राथमिकी देखने के बाद कहा कि लगाए गए आरोपों से स्पष्ट है कि याची सशस्त्र हिंसक भीड़ में शामिल था। जिसने पुलिस पर हमला किया और उनके कई वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया। सार्वजनिक सम्पत्ति नष्ट की गई। पांच फरवरी 2020 को यह घटना काफी देर तक जारी रही। आरोपों की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने जमानत देने से इंकार कर दिया है।

डीएम ने स्वरूपरानी अस्पताल का किया निरीक्षण, बैठक कर दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

प्रयागराज। जिलाधिकारी भानु चन्द्र गोस्वामी बुधवार को स्वरूपरानी अस्पताल पहुंचकर अस्पताल का निरीक्षण किया तथा बैठक कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के जो भी मरीज अस्पताल में आएं, उनको तत्काल भर्ती करते हुए उनका इलाज शीघ्रता से शुरू कर दिया जाये, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही न होने पाये। जिलाधिकारी ने इसके लिए अलग से एक कोविड हेल्प डेस्क बनाये जाने का निर्देश दिया है। उन्होंने पीडब्लूडी को हेल्प डेस्क के कार्य को तत्काल पूर्ण कराये जाने का निर्देश दिया है। बैठक में जिलाधिकारी ने अस्पताल में भर्ती एक-एक कोविड मरीजों की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि भर्ती मरीजों को किसी भी प्रकार की असुविधा न होने पाये, उनके खान-पान एवं इलाज की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित रहे। उन्होंने कहा कि भर्ती मरीजों का बेहतर से बेहतर इलाज किया जाये। अस्पताल में बन रहे एचईडीयू वार्ड का निरीक्षण किया तथा इस कार्य को शीघ्रता से पूर्ण कर शुरू कराये जाने का निर्देश दिया है। जिलाधिकारी ने नई बिल्डिंग में बनाये जा रहे 200 बेड के आइशोलेशन वार्ड एवं आईसीयू के संचालन के सम्बंध में समस्त औपचारिकताएं शीघ्रता से पूर्ण कराते हुए तत्काल क्रियाशील किए जाने का निर्देश दिया है।

बैठक में आवश्यक दिशा निर्देश देते जिलाधिकारी

अखण्ड भारत संदेश के लिए स्वामी श्री योगी सत्यम कियायोग आश्रम एवं अनुसंधान सस्थान झूंसी, प्रयागराज 211019 से प्रकाशित एवं रामा प्रिंटिंग प्रेस 53/25/1ए बेली रोड नया कटरा प्रयागराज से मुद्रित।

मुद्रक/प्रकाशक

स्वामी श्री योगी सत्यम

पी0आर0बी0 एक्ट के अन्तर्गत समाचारों के चयन के लिए उत्तरदायी। इस समाचार पत्र में प्रकाशित समस्त समाचारों से संबंधित विवादों का न्याय क्षेत्र प्रयागराज होगा। आरएनआई नं0: UPHIN2001/9025

आंधी हो या पानी रूक नहीं सकते कदम मेरे : आचार्य लक्ष्मण

प्रयागराज। विपदा को अवसर में बदलना भाजपा के कार्यकर्ताओं को खूब आता है। आंधी हो या पानी कार्यकताओं के कदम नहीं रूकते। भाजपा का कार्यकर्ता कार्य ना मिलने से नाराज होता है। उक्त बातें भाजपा यमुनापार जिला पदाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक में बुधवार को उत्तर प्रदेश के नवनियुक्त उपाध्यक्ष व एमएलसी लक्ष्मण आचार्य ने कही। बैठक में यमुनापार जिले के 1528 बूथों की मंडलवार समीक्षा करते हुए पार्टी के आगामी कार्य योजनाओं के बारे में जानकारी दी। जिलाध्यक्ष विभवनाथ भारती के हास्पिटल में भर्ती होने के कारण जिला उपाध्यक्ष शोभनारायन द्विवेदी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता व संचालन जिला महामंत्री विजय शंकर शुक्ल ने किया। जिला के बूथ सत्यापन प्रमुख राजेश शुक्ला ने कार्यों से अवगत कराया। इस अवसर पर सविता त्रिपाठी, त्रिवेणी प्रसाद पाण्डेय, विक्रमाजीत मौर्य, रामेश्वर पटेल, दिलीप कुमार चतुवेर्दी, अजीत प्रताप सिंह, जगदीश सिंह यादव, राजेश्वरी तिवारी आदि रहे।

क्रियायोग सन्देश

प्रयागराज रविवार, 27 अगस्त, 2020

विश्व शांति के लिए युद्ध के स्थान पर विश्व बन्धुत्व की भावना का विस्तार

Gandhi with textile workers at Darwen, Lancashire, September, 1931

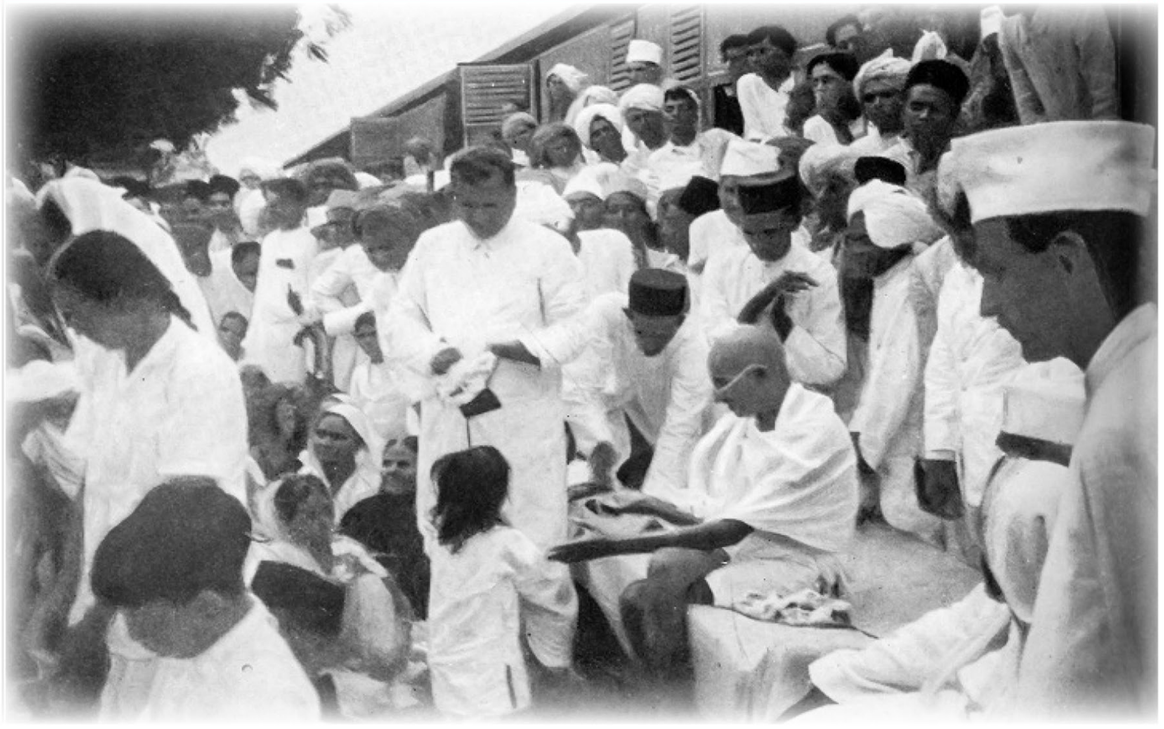

Collecting money for Harijan Fund on railway platform, Bhavnagar, July 1934

मैं देखता हूँ कि ध्वंस के बीच में जीवन विद्यमान है। इसलिए ध्वंस से भी बड़ा कोई विधान अवश्य है। केवल उस विधान के अन्तर्गत ही सुव्यवस्थित समाज का अस्तित्व संभव हो सकता है और जीवन जीने योग्य बन सकता है।

''यदि यही जीवन का विधान है, तो अपने दैनिक जीवन में हमें उसका पालन करना चाहिए। जहाँ कहीं युद्ध हो, जहाँ कहीं किसी विरोधी पक्ष से सामना हो, हमें प्रेम से ही उस पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। मैंने देखा है कि प्रेम के विधान ने मेरे जीवन में अनेक प्रश्नों का समाधान किया है, जो ध्वंस के विधान से कभी नहीं हो पाया है।''

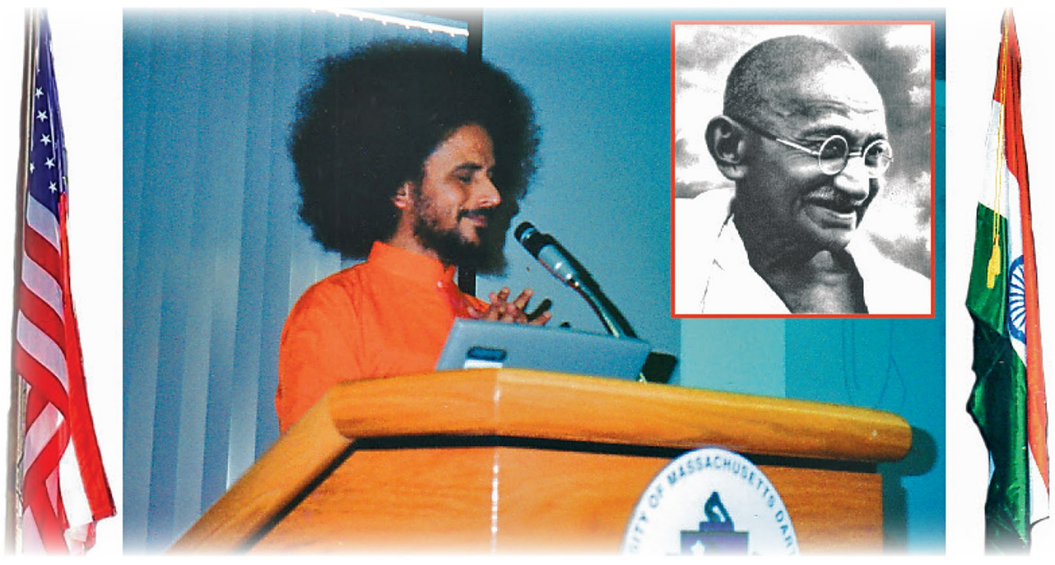

Guruji Swami Shree Yogi Satyam at University of Massachusetts

इतिहास इस बात का साक्षी है कि मनुष्य की समस्याएँ पाशविक शक्ति के प्रयोग से हल नहीं हुई है। प्रथम विश्वयुद्ध के रोमांचकारी भयानक कर्मफल के रूप में ही द्वितीय विश्वयुद्ध ने जन्म लिया। केवल विश्व बंधुत्व-भाव की उष्णता ही द्वितीय विश्व युद्ध के भयानक कर्मफल के हिमखंड को पिघला सकती है, अन्यथा सम्भव है कि उससे तृतीय विश्वयुद्ध का जन्म हो। बीसवीं सदी की अमंगलत्रयी विवादों के निबटारे के लिए मानवी विवेक के बदले जंगली उपायों के अवलंबन से तो पृथ्वी जंगल बन कर रह जायेगी। यदि जीवन में भाईचारा स्थापित नहीं हो सका, तो भयानक मृत्यु की गोद में भाईचारा होगा। ईश्वर ने प्रेमपूर्वक मनुष्य को अणु शक्ति के आविष्कार की जो प्रेरणी दी है, वह इस प्रकार के घृणित व्यवहार के लिए नहीं!

युद्ध और अपराध कभी लाभप्रद नहीं होते। अरबों डालर विस्फोटक पदार्थों का धुआँ बन कर शून्य में मिल जाता है। इस धनराशि से तो रोग और दारिद्र्य से पूर्णत: मुक्त एक नये विश्व का ही निर्माण हो सकता था। भय, अराजकता, अकाल और महामारी आदि के प्रलय नृत्यों का रंगमंच न बन कर पृथ्वी शान्ति, समृद्धि और ज्ञान-प्रसार का विस्तीर्ण क्षेत्र बन जाती।

गाँधी जी की अहिंसा की पुकार मनुष्य की सर्वोच्च चेतना का स्पर्श करती है। आज राष्ट्रों को मृत्यु के साथ नहीं वरन् जीवन के साथ, विध्वंस के साथ नहीं वरन् निर्माण के साथ, घृणा के साथ नहीं किन्तु प्रेम के सर्जनात्मक चमत्कारों के साथ सम्बन्ध स्थापित करना चाहिए।

- योगी कथामृत

Importance of Universal Brotherhood Necessary for World Peace

" I have found that life persists in the midst of destruction. Therefore, there must be a higher law than that of destruction. Only under that law would well-ordered society be intelligible and life worth living."

If that is the law of life we must work it out in daily existence. Wherever there are wars, wherever we are confronted with an opponent, conquer by love. I have found that the certain law of love has answered in my own life as the law of destruction has never done."

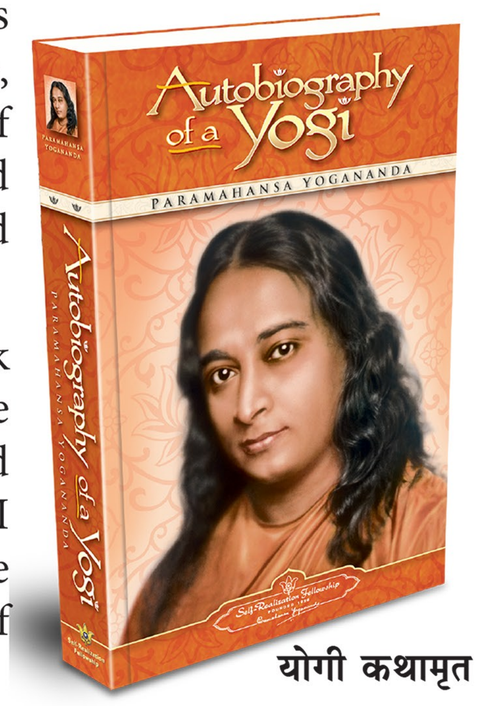

योगी कथामृत

Gandhiji nursing the leper patient Parchure Shastri, Segaon, 1939

"War and crime never pay. The billions of dollars that went up in the smoke of explosive nothingness would have been sufficient to have made a new world, one almost free from disease and completely free from poverty. Not an earth of fear, chaos, famine, pestilence, the danse macabre, but one broad land of peace, of prosperity, and of widening knowledge."

"The non-violent voice of Gandhi appeals to man's highest conscience. Let nations ally themselves no longer with death, but with life; not with destruction, but with construction; not with the Annihilator, but with the Creator.

Non-violence is the natural outgrowth of the law of forgiveness and love. "If loss of life becomes necessary in a righteous battle," Gandhi proclaims, "one should be prepared, like Jesus, to shed his own, not others', blood. Eventually there will be less blood spilt in the world."

" I call myself a nationalist, but my nationalism is as broad as the universe. It includes in its sweep all the nations of the earth. My nationalism includes the well-being of the whole world. I do not want my India to rise on the ashes of other nations. I do not want India to exploit a single human being. I want India to be strong in order that she can infect the other nations also with her strength. Not so with a single nation in Europe today; they do not give strength to the others."

- Gandhiji's thoughts and quotations as given in Autobiography of a Yogi by Paramahansa Yogananda